गेहूं का वसूली मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव

1774. **श्री राघवजी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कृषि मूल्य आयोग ने गेहूं की उत्पादन लागत किस-किस तारीख को निर्धारित की थी और गेहूं की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत, रुपयों में, कितनी निर्धारित की थी;

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग इस समय गेहूं की उत्पादन लागत निर्धारित करने के मामले पर पुन: विचार कर रहा है और यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या सरकार वर्ष 1978-79 के लिए गेहूं के वसूली मूल्य अथवा समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) वर्ष 1977-78 के दौरान सरकार द्वारा अथवा भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितने गेहूं की वसूली की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जैसा कि गेहूं की मूल्य निर्धारण तथा वसूली नीति सम्बन्धी कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्टों, जिन्हें प्रति वर्ष संसद् के पुस्तकालय में रखा जाता है, से विदित होगा कि आयोग गेहूं की मूल्य नीति पर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय गेहूं की उत्पादन लागत निर्धारित नहीं करता है फिर भी यह अन्य बातों के साथ-साथ गेहूं की उत्पादन-लागत के उपलब्ध अनुमान को ध्यान में रखता है।

(ख) और (ग). 1978-79 विपणन मौसम के लिए गेहूं की मूल्य नीति पर कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जाएगा और विपणन मौसम के शुरू होने से पहले गेहूं के वसूली। समर्थन मूल्य सम्बन्धी निर्णय की घोषणा किए जाने की सम्भावना है।

(घ) 1977-78 रबी विपणन मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में 51.6 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई है।

Master Plan for Minor Irrigation in Tribal Areas

1755. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have proposed master plan for the development of minor irrigation in tribal areas in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The States have been asked to prepare Master Plans for development of irrigation in tribal areas.

(b) The Master Plans would include, apart from minor irrigation, major-medium schemes also and would provide for implementation of all minor irrigation schemes in a period of 5 years, and that of major-medium irrigation schemes in a period of 15 years.

High Powered Committee on Land Ceiling Laws

1776 SHRI BASANT SATHE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Land Ceiling Acts formulated by the State Governments are defective;